Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/Pfiofficial

प्रेस रिलीज़

7 मार्च 2020
नई दिल्ली

पॉपुलर फ्रंट की मीडिया संस्थानो से अपीलः ईमानदारी से खड़े हों और खबरों की नाकाबंदी का विरोध करें

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम ने मीडिया को जारी अपने एक बयान में दो मलयालम न्यूज चौनलों –एशिया न्यूज़ और मीडिया वन– पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्लिम विरोधी नरसंहार को दिखाने के कारण नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 48 घंटे तक प्रतिबंध लगाए जाने को लोकतंत्र के चौथे और महत्वपूर्ण स्तंभ और भारतीय संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खुला हमला करार दिया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों चौनलों ने 25 फरवरी को हुई हिंसा को इस तरह से दिखाया है जिसमें ''धार्मिक स्थलों पर हमले को उजागर किया गया है और एक विशेष समुदाय की तरफदारी की गई है।'' ओ.एम.ए. सलाम ने इस अमल को उन विजुअल मीडिया को डराने का एक तरीका बताया है जो आज भी आरएसएस/बीजेपी और उनकी सरकारों की गलत हरकतों पर आज़ादी के साथ और आलोचनात्मक तरीके से पत्रकारिता करने का साहस करती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब तक कहां सोई हुई थी जब अधिकतर हिंदी और अंग्रेजी 'गोदी मीडिया' लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों, उनके प्रयासों, संगठनों और नेताओं के खिलाफ ज़हर उगल रही थीं। केंद्र सरकार दक्षिण भारत के स्थानीय मीडिया घरानों को खास तौर से निशाना बना रही है, क्योंकि वह भारत के अन्य क्षेत्रों के मीडिया घरानों के मुकाबले अपनी आज़ादी का पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार और उसके बाद राज्य सरकार ने लगातार कई सालों तक मलयालम दैनिक 'तेजस' को विज्ञापन देने से मना कर दिया था और आखिरकार वह दैनिक बंद हो गया। लेकिन इस अत्याचार के खिलाफ केवल गिनी–चुनी मीडिया ने ही थोड़ी आवाज़ उठाई थी।

ओ.एम.ए. सलाम ने कहा कि भागवत–मोदी–शाह की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आज सूचना नाकाबंदी मंत्रालय बन गया है। उन्होंने एशिया न्यूज़ और मीडिया वन के साथ एकजुटता जताई जिन्हें मौजूदा तानाशाही सरकार द्वारा निशाना बनाया गया है।

डॉ. मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली